भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 5 * दि. 1 से 15 अगस्त 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

भाईंदर पूर्व गोडदेव में बस स्टॉप गायब

यात्रियों को करना पड रहा है भारी परेशानी का सामना

भाईंदरः भाईंदर के गोडदेव नाका इलाके से पिछले कुछ महीनों में अचानक बस स्टॉप गायब होने की बात सामने आई है। इसकी वजह से धूप और बारिश में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मीरा-भाईंदर शहर के लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम के परिवहन विभाग ने अलग-अलग जगहों पर बस स्टॉप बनाए हैं। इन स्टॉप्स पर मीरा-भाईंदर नगर निगम (MBMT) की बसों के साथ-साथ बेस्ट (BEST) की बसें भी रुकती हैं। इन बसों से सफर करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है।

भाईंदर का गोडदेव नाका स्थित नगर निगम का यह पुराना बस स्टॉप सबसे व्यस्त (भीड़भाड़ वाले) बस स्टॉप्स में से एक है। इस बस स्टॉप के निर्माण, देखभाल और मरम्मत के लिए प्रशासन ने अब तक करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से इस बस स्टॉप को हटा दिए जाने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है और भ्रम का माहौल बना हुआ है। बारिश या कड़क धूप में आखिर कहाँ खड़े हों, यह सवाल यात्रियों के सामने खड़ा हो गया है। इसलिए यात्री मांग कर रहे हैं कि यहाँ तुरंत नया बस स्टॉप बनाया जाए।

इसी बीच, परिवहन समिति के सभापति राजकुमार मिश्रा ने हाल ही में इस जगह का निरीक्षण किया और दावा किया कि जल्द ही यहाँ नया बस स्टॉप बनाया जाएगा।

प्रशासन की ओर से नोटिस जारी

गोडदेव बस स्टॉप के पास बनी एक खतरनाक इमारत पर कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान इमारत का मलबा बस स्टॉप पर गिर गया। इस हादसे में बस स्टॉप को भारी नुकसान पहुँचा, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। इस मामले में संबंधित इमारत के मालिक को नोटिस भेजकर नया बस स्टॉप बनाकर देने को कहा गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी दिनेश कानगुडे ने जानकारी दी कि अगर आने वाले कुछ दिनों में बस स्टॉप नहीं बनाया गया, तो आरोपी के खिलाफ सीधे मामला दर्ज किया जाएगा।

मीरा- भाईंदर व चंदौली में शिक्षा-सम्राट पंडित लल्लन तिवारी का जन्मदिन 20 जुलाई को धूमधाम से मनाया गया

सुभाष पांडेय

भाईंदर। ' राहुल ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेज ' के संस्थापक अध्यक्ष पंडित लल्लन रामाधार तिवारी का जन्मदिन हर वर्ष धूमधाम से 20 जुलाई को मीरा-भाईंदर समेत, नालासोपारा, पालघर, पूना, चंदौली महुवरकला में धूमधाम से मनाया जाता रहा है। जीवंत के 76 वसंत देख चुके पंडित लल्लन तिवारी का जन्म उत्तरप्रदेश के जिला चंदौली, ग्राम-महुवरकला में एक ' ब्राह्मण संपन्न एवं समृद्धि परिवार' में जन्म हुवा। उनके पिताजी मुंबई के दादर ' कीर्तिकर मार्केट ' में उद्यम करते थे। लल्लन तिवारी बचपन से ही बड़े ही प्रतिभावान , भाग्यशाली, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें बचपन से ही ' सफेद रंग ' बहुत पसंद था। ' आशावादी विचारधारा ' को अपने जीवन में उतार रखा था। दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चयी , कर्मयोगी पंडित लल्लन तिवारी ने अपने भाग्य को खुद ही बनाया। वे कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। दिन-रात जी तोड़ मेहनत कर आज ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं।

भाईंदर (पूर्व) में दादर से आने के बाद ' राहुल ग्रुप ' के नाम से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। कई बिल्डिंग, टॉवर बनाये। जमीन, लेन-देन के चलते उनके ऊपर कई बार ' जानलेवा हमला ' हुवा। उन पर गोलियां चलीं। वे बाल-बाल बच गये। ' राहुल ग्रुप ' कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ सन 1992 में स्कूल चलाने की शुरुवात की। ' राहुल पार्क ' में व्याप्त ' मदर मेरी स्कूल की शुरुवात की। उसके बाद लगातार न जाने कि त ने स्कू ल स - कॉ ले जे स है। आज उनके 65 से अधिक शि क्षा - सं स्था न चल रहे हैं। 2000 से अधिक स्टॉफ हैं। 70,000 हजार से अधिक छात्र शिक्षा-ग्रहण कर रहे हैं। पंडित लल्लन तिवारी की धर्मपत्नी कान्तिदेवी , पुत्र राहुल, पुत्रवधु कृष्णा, पौत्र उत्सव तिवारी स्कूल-कॉलेज के ट्रस्टी हैं तथा स्कूल-कॉलेज सुचारू रूप से चला रहे हैं। उनके जन्मदिन पर ' भायंदर सन ' मीडिया परिवार हार्दिक बधाईयां एवं शुभकामनाएं देता है।

सड़कों की बदहाली पर प्रशासन और विपक्ष दोनों कटघरे में काशीमीरा से घोडबंदर तक 12 किमी जाम

भाईंदर : मानसून के बीच मीरा-भाईंदर और ठाणे-घोडबंदर मार्ग की बदहाल सड़कों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, ठाणे-घोडबंदर रोड और शहर की आंतरिक सड़कों पर गहरे गड्ढों के कारण यातायात व्यवस्था चरमरा गई है. सोमवार को नायगांव पूर्व स्थित सनसिटी होटल से घोडबंदर के फाउंटेन होटल तक करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबा भीषण ट्रैफिक जाम लग गया. सामान्यतः 20 मिनट में पूरा होने वाला सफर लोगों को 2 से 3 घंटे में तय करना पड़ा. गड्ढों, भारी वाहनों के दबाव और लगातार खराब होती सड़कों के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है. मीरा-भाईंदर मुख्य मार्ग, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग और ठाणे-घोडबंदर रोड पर हालात सबसे अधिक गंभीर बताए जा रहे हैं. जगह-जगह बने गहरे गड्ढों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, वहीं रोजाना हजारों वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. नागरिकों का आरोप है कि संबंधित अधिकारी निरीक्षण और समीक्षा बैठकों तक ही सीमित हैं, जबकि स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही.

यातायात व्यवस्था प्रभावित

दूसरी ओर, मनपा प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का एक कारण हैं, हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि खराब निर्माण गुणवत्ता और समय पर मरम्मत नहीं होने से स्थिति और बिगड़ी है. मनपा ने करोड़ों रुपये खर्च कर कुछ प्रमुख सड़कों का कंक्रीटीकरण कराया है, लेकिन धनाभाव के चलते अधिकांश डामर सड़कें अब भी बदहाल हैं. इस वर्ष मानसून शुरू होने के कुछ ही दिनों में कई सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे उभर आए, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई.

वाहन चालकों का आरोप है कि मनपा, एमएमआरडीए और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कई स्थानों पर केवल औपचारिक पैचवर्क कर रहे हैं. बारिश की तीव्रता कम होने के बावजूद स्थायी मरम्मत कार्य अपेक्षित गति से शुरू नहीं हो पाया है. गड्ढों की समस्या को लेकर अब सत्ताधारी और विपक्ष दोनों सवालों के घेरे में हैं. नागरिकों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन करने वाले विपक्षी दल भी इस गंभीर समस्या पर अपेक्षित आक्रामकता नहीं दिखा रहे हैं.

मनपा प्रशासन, एमएमआरडीए और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को युद्धस्तर पर स्थायी मरम्मत कार्य शुरू कर सड़कें सुरक्षित एवं गड्ढामुक्त बनाने तथा सुगम यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है

-सज्जी आई. पी, सामाजिक कार्यकर्ता

संपादकीय

निजी आजादी पर रोक क्यों

देश में गाहे-बगाहे असहमति के अधिकार और व्यक्तिगत आजादी पर अंकुश लगाने के प्रयासों पर चर्चा होती ही रहती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के हालिया बयानों ने इस मुद्दे को एक बार फिर सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाया है। दरअसल, पिछले हफ्ते भोपाल स्थित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान देते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में चौदह युवाओं की गिरफ्तारी और उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने के मुद्दे पर तल्ख सवाल उठाए थे। दरअसल, मार्च 2026 में इन युवाओं पर आरोप लगा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में नाव की सवारी के दौरान इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाई थी और बिरयानी के बचे अवशेष नदी में डाल दिए थे। स्थानीय स्तर पर मामले के तूल पकड़ने के बाद इन चौदह युवाओं को गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि गंगा नदी के ऊपर या किनारे चिकन बिरयानी खाना कोई कानूनी अपराध नहीं है। उनका कहना था कि किसी भी कानून में ऐसी गतिविधि पर रोक नहीं है। जस्टिस भुइयां ने इसके साथ ही शांतिपूर्ण असहमति को अपराध की श्रेणी में लाने के बढ़ते चलन पर भी चिंता जताई। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की सेहत से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया है। तो सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार लोगों की निजी पसंद, अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध करने के अधिकार पर रोक लगाने में हद से आगे बढ़ रही है? क्या नागरिकों को उन कामों के लिये उनकी आजादी से वंचित किया जा सकता है जो कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में नहीं आते? हाल-फिलहाल के घटनाक्रमों के आलोक में बीस जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की राय से असहमत होना मुश्किल ही कहा जाएगा। उनकी राय थी कि असहमति के लिये जगह कम होती जा रही है।

दरअसल, हाल के वर्षों में अक्सर देखा गया है कि देश में पर्यावरण कार्यकर्ता, छात्र, विभिन्न संगठन और दूसरे नागरिक जो असहमति जताते हैं, उन्हें अक्सर आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार प्रतिरोध के स्वरों की अनसुनी कर देती है। हालांकि,देर-सवेर अदालतें, अक्सर मामले के कानूनी प्रक्रिया में आने के बाद उन्हें राहत दे देती हैं। लेकिन अक्सर जमानत में होने वाली देरी और सख्त शर्तें अपने आप में सजा का ही एक रूप बन सकती हैं। निस्संदेह, इस आलोक में देश की न्यायपालिका को भी, जो संवैधानिक अधिकारों की संरक्षक भी है, अपनी भूमिका की नये सिरे से समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ न्यायिक फैसलों से ही आजादी की रक्षा नहीं की जा सकती। निर्विवाद रूप से प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा उपाय भी मायने रखते हैं क्योंकि प्रक्रिया खुद नागरिकों के जीवन पर असर डालती है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की न्यायिक जवाबदेही की मांग बहुत सही समय पर सामने आई है। निर्विवाद रूप से आलोचना से अदालतें कमजोर नहीं होती हैं वरन जब उसके फैसलों की खुलकर समीक्षा की जाती है तो वे और मजबूत होती हैं। संस्थाओं में जनता का भरोसा उसकी कार्यशैली, तर्क और विनम्रता से ही आता है, न कि जांच-पड़ताल से बचने की प्रवृत्ति से। न्यायमूर्ति ने अपनी बात कहकर सार्वजनिक विमर्श के लिये इस मुद्दे को रख दिया है। अब देश के विभिन्न पक्षों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र तभी अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ सकता है जब नागरिकों में वैचारिक आजादी की पर्याप्त जगह हो। जब किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक बेबाकी से अपने हित से जुड़े सवाल पूछ सकें और सत्ता के समक्ष निर्भीक होकर सच बोलने के लिये आजाद हों तो इससे सही अर्थों में लोकतंत्र की मूल भावनी पुष्ट ही होती है। देश के नीति-नियंताओं को भी न्यायमूर्ति के उद्गारों पर चिंतन-मनन करने की जरूरत है।

गुस्से व उम्मीद से आंदोलन की कामयाबी

यह जीत युवा भारत की ताकत को रेखांकित करती है। जब आकांक्षाएं टूटती हैं, तो गुस्सा संगठित हो जाता है। सीजेपी ने दिखाया कि डिजिटल युग में भी सड़क और सोशल मीडिया का संयोजन प्रभावी हो सकता है।

गत 25 जुलाई को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा जंतर-मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के छात्र आंदोलन के दबाव का सीधा नतीजा था। युवाओं ने जो मांग रखी थी, वह लगभग पूरी तरह स्वीकार कर ली गई। प्रदर्शन समाप्त कर दिए गए। यह घटना स्वतंत्र भारत के छात्र आंदोलनों के इतिहास में एक उल्लेखनीय सफलता के रूप में दर्ज होगी।

सीजेपी आंदोलन की शुरुआत साधारण नहीं थी। इसे अमेरिका में रह रहे इंडो-अमेरिकन अभिजीत दीपके ने शुरू किया। बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' कहे जाने वाले बयान को उन्होंने व्यंग्य के रूप में अपनाया और सोशल मीडिया के जरिए एक नई भाषा दी। यह डिजिटल व्यंग्य और सड़क पर धरने का मिश्रण था। पारंपरिक छात्र संगठनों से अलग, यह शुरू में गैर-दलीय और आकांक्षा केंद्रित था। एनईईटी-यूजी 2026 के पेपर लीक ने इसे भड़काया था। परीक्षा की अनियमितताओं, छात्र आत्महत्याओं और व्यापक बेरोजगारी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया।

हालांकि, इस आंदोलन को व्यापक और टिकाऊ बनाने में पारंपरिक छात्र संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) समेत कई छात्र मोर्चों ने सीजेपी के साथ सक्रिय समर्थन दिया। इन संगठनों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और शहरों में प्रदर्शन, रैलियां और बंद के आह्वान किए। उनकी संगठनात्मक ताकत ने आंदोलन को सिर्फ जंतर-मंतर तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि पूरे देश में फैलाया।

इसके अलावा, इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भी लगातार दबाव बनाए रखा। संसद में विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सत्र बाधित किया। कई नेता जंतर-मंतर पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब प्रदर्शनकारियों और सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान धक्का-मुक्की हुई, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। राहुल गांधी सहित कई नेताओं को पुलिस ने हटाया और हिरासत में लिया। इन घटनाओं ने आंदोलन को और तीखा बना दिया तथा सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। लंबे समय तक चुप्पी साधे रखने वाली मोदी सरकार को अंततः जवाब देना पड़ा। छात्र संगठनों व विपक्षी दलों के संयुक्त दबाव ने आंदोलन को साधारण धरने से कहीं आगे बढ़ा दिया।

स्वतंत्र भारत में छात्र आंदोलन अक्सर गुस्से और उम्मीद का मिश्रण रहे हैं। 1970 के दशक का जेपी

आंदोलन आपातकाल के खिलाफ था और उसने लोकतंत्र की बहाली में भूमिका निभाई। 2011 का अन्ना हजारे का भारत भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन मध्यम वर्ग को सड़कों पर लाया और राजनीतिक परिदृश्य बदलने में सफल रहा। मंडल आंदोलन ने सामाजिक न्याय की दिशा बदली। इन आंदोलनों की तुलना में सीजेपी की सफलता ज्यादा तेज और ठोस दिखता है। प्रधान का इस्तीफा एक स्पष्ट और त्वरित नतीजा है।

दुनिया भर में परीक्षा लीक की घटनाएं बार-बार होती रही हैं। चीन, मिस्र, बांग्लादेश और अमेरिका में भी ऐसे घोटाले सामने आए। लेकिन भारत में पैमाना बहुत बड़ा था। करोड़ों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ा। सीजेपी ने इन लीक को युवा बेरोजगारी से जोड़कर देखा। ग्रेजुएट्स में लगभग 40 प्रतिशत को उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती। यही वजह थी कि आंदोलन सिर्फ परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं रहा।

वैश्विक तुलना भी दिलचस्प है। बांग्लादेश के 2024 के छात्र आंदोलन ने कोटा व्यवस्था के खिलाफ शुरू होकर सरकार बदल दी। चिली के 2011 छात्र आंदोलन ने शिक्षा सुधारों को मजबूर किया। हांगकांग के 2019 आंदोलन में युवाओं ने डिजिटल रणनीति अपनाई। सीजेपी ने इन सबकी कुछ खूबियों को अपनाया — व्यंग्य, सोशल मीडिया और निरंतर दबाव। लेकिन भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में यह दबाव ज्यादा प्रभावी साबित हुआ।

अब सवाल यह है कि आगे क्या? सरकार ने कुछ मांगें स्वीकार की हैं — मुआवजा, मामलों की वापसी और सुधारों का वादा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या परीक्षा प्रणाली में स्थायी बदलाव आएंगे? क्या कोचिंग संस्कृति और नौकरी के संकट पर ध्यान दिया जाएगा? इतिहास बताता है कि छात्र आंदोलन अक्सर त्वरित सफलता पाते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सुधारों के लिए निरंतर दबाव जरूरी होता है।

यह जीत युवा भारत की ताकत को रेखांकित करती है। जब आकांक्षाएं टूटती हैं, तो गुस्सा संगठित हो जाता है। सीजेपी ने दिखाया कि डिजिटल युग में भी सड़क और सोशल मीडिया का संयोजन प्रभावी हो सकता है। साथ ही, पारंपरिक छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के सक्रिय सहयोग ने इसे और मजबूत बनाया। यह आंदोलन सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की कहानी नहीं है। यह शासन की जवाबदेही, मेरिट की रक्षा और युवाओं के सपनों की रक्षा की कहानी है।

आंदोलन की कामयाबी

नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों ने जो कई सप्ताह लंबा आंदोलन चलाया,उसकी तार्किक परिणति सबके सामने है। सरकार को छात्र आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। जिसके फलस्वरूप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। एक बार फिर मोदी सरकार को आंदोलनकारियों के दबाव में फैसला लेना पड़ा। भाजपा के नेता कहते रहे हैं कि इस सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हुआ करते। युवाओं के इस आंदोलन ने किसान आंदोलन की याद ताजा कर दी, जब सरकार को किसानों के एक साल चले आंदोलन के बाद तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। वहीं सरकार को उस संकट को स्वीकार करना पड़ा, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दशकों से शिकंजा कसे हुआ था। बहरहाल, सड़कों पर उतरे छात्रों के आंदोलन से साफ संदेश सामने आया कि अब भारत के युवा उस सिस्टम से जवाबदेही मांग कर रहे हैं, जो उनके भविष्य का निर्धारण करता है। एक और बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि युवाओं के इस आंदोलन ने देश के समक्ष मौजूदा दो सबसे बड़ी चुनौतियों- शिक्षा और बेरोजगारी को फिर सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों पर चर्चा पहले नहीं हुई। लेकिन यह महज नीतियां बनाने और चुनावी भाषणों में चर्चा तक सीमित रह गया था। विडंबना यह है कि देश में एक के बाद एक आई सरकारों ने कभी इस चुनौती का सीधे तौर पर मुकाबला नहीं किया। वहीं इस छात्र आंदोलन ने यह भी साबित किया है कि हम जिस पीढ़ी को अक्सर महज 'डिजिटल दुनिया में खोई हुई' पीढ़ी मानते रहे हैं, वह पीढ़ी संस्थागत सुधारों के लिये पूरी चेतना के साथ सामने आ सकती है। निस्संदेह, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद केंद्र को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन सुधार की उसकी इच्छा महज मंत्रियों और अधिकारियों को हटाने तक ही सीमित न रहे। ऐसी स्थिति में जब शिक्षा में सीमित सीटों और नौकरियों के लिये लाखों प्रतियोगी कड़ा मुकाबला करते हैं, सरकार सोचे कि प्रवेश परीक्षाओं को कैसे पारदर्शी व फूलप्रूफ बनाया जाए। इन्हें कितनी जिम्मेदारी के साथ आयोजित किया जाता है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। निस्संदेह, परीक्षा में धोखाधड़ी के खिलाफ प्रस्तावित कठोर कानून, फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा आवश्यक कदम हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कठोर कानून मात्र से बिगड़ा हुआ ढांचा ठीक नहीं होगा। वास्तव में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सार्वजनिक परीक्षाओं के स्वरूप में पारदर्शिता, तकनीकी सुरक्षा और स्वतंत्र निगरानी जरूरी है। संसद में इन सुधारों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी समझ ले कि छात्रों के भविष्य को राजनीतिक बाजीगरी का अखाड़ा नहीं ही बनाया जाना चाहिए। भारत आज एक युवा देश है, जिसकी आधी से ज्यादा आबादी तीस साल से कम उम्र वाली है। ऐसे में हमें एक ऐसे शिक्षा तंत्र की जरूरत है, जो युवाओं का भरोसा कायम करे। साथ ही योग्य प्रतिभागियों को न्याय मिले। एक संदेश साफ है कि अब जेन-ज़ी को गंभीरता से लेना होगा।

दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो-9 को मिली रफ्तार

बिजली लाइन शिफ्टिंग के लिए 4 घंटे के शटडाउन को मंजूरी

दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो लाइन-9 परियोजना के निर्माण में आ रही एक बड़ी तकनीकी बाधा दूर हो गई है। भाईंदर पश्चिम स्थित शहीद भगत सिंह मेट्रो स्टेशन

के पास गुजर रही उच्च वोल्टेज बिजली लाइन पर आवश्यक कार्य के लिए राज्य सरकार और अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने रात में चार घंटे के नियोजित शटडाउन को मंजूरी दे दी है। इससे लंबे समय से रुका स्टेशन निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

उच्च वोल्टेज लाइन बनी थी बाधा

एमएमआरडीए के अनुसार, मैक्सस मॉल क्षेत्र के पास गुजर रही उच्च वोल्टेज बिजली लाइन के कारण सुरक्षा कारणों से स्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य रोके गए थे। अब निर्धारित रात्रिकालीन शटडाउन के दौरान आवश्यक तकनीकी कार्य पूरे किए जाएंगे, जिससे निर्माण में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी।

बिजली आपूर्ति पर नहीं पड़ेगा असर

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शटडाउन केवल निर्माण कार्य के लिए होगा। इस दौरान संबंधित हाई-वोल्टेज लाइन की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी, लेकिन आम उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैकल्पिक फीडर के माध्यम से क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

दूसरे चरण का काम अंतिम दौर में

एमएमआरडीए के मुताबिक, मीरा भाईंदर मेट्रो-9 के दूसरे चरण में काशीगांव से सुभाष चंद्र बोस मैदान तक अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शहीद भगत सिंह मेट्रो स्टेशन के पास बचा हुआ कार्य अब तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके बाद अंतिम निर्माण, परीक्षण और अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर मेट्रो ट्रायल शुरू करने की योजना है।

वर्षांत तक सेवा शुरू होने की संभावना

प्राधिकरण का कहना है कि सभी आवश्यक मंजूरियां समय पर मिलने पर काशीगांव से सुभाष चंद्र बोस मैदान तक मेट्रो-9 का दूसरा चरण इस वर्ष के अंत तक यात्रियों के लिए शुरू किया जा सकता है। इस कॉरिडोर के चालू होने से मीरा-भाईंदर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों दैनिक यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलेगा।

शौचालय बदहाल यात्री बेहाल... रेलवे बेखबर!

मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क के सबसे व्यस्त स्टेशनों में शामिल भायंदर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले इस स्टेशन पर स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी बदहाल हालत में है। स्टेशन पर पैली गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्था रेलवे प्रशासन के विकास और यात्री सुविधाओं के दावों की पोल खोल रही है। यात्रियों का आरोप है कि बड़े-बड़े विकास कार्यों का प्रचार तो किया जा रहा है, लेकिन रोजमर्रा की आवश्यक सुविधाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

छह प्लेटफॉर्म वाले भायंदर स्टेशन से प्रतिदिन लगभग १.८० लाख यात्री सफर करते हैं, जबकि पूरे स्टेशन पर केवल दो शौचालय ही उपलब्ध हैं। इसके कारण यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों, को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामना संवाददाता द्वारा किए गए मौके के निरीक्षण में महिला शौचालय की स्थिति बेहद दयनीय मिली। दो शौचालयों के दरवाजे गायब थे, जबकि एक अन्य शौचालय में टूटा-फूटा सामान भरकर उसे अनुपयोगी बना दिया गया था। उपयोग में मौजूद शौचालय भी गंदगी और दुर्गंध से भरा मिला। नियमित सफाई, कूड़ेदान और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव साफ दिखाई दिया।

पुरुष शौचालय की हालत भी इससे अलग नहीं थी। पानी की व्यवस्था ठप मिली, वॉश बेसिन टूटा हुआ था, दरवाजे क्षतिग्रस्त थे और बाल्टी-मग जैसी सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं। तेज दुर्गंध के कारण वहां कुछ देर ठहरना भी मुश्किल था। यात्रियों का कहना है कि जब शौचालय उपयोग के लिए शुल्क वसूला जा रहा है, तब ऐसी बदहाल व्यवस्था रेलवे प्रशासन की लापरवाही का खुला प्रमाण है।

शौचालय के बाहर शुल्क वसूलने वाली महिला ने बताया कि यहां कोई स्थायी कर्मचारी तैनात नहीं है। अलग-अलग लोग कुछ घंटों के लिए बैठकर यात्रियों से दो से पांच रुपये वसूलते हैं और फिर चले जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि शौचालयों की देखरेख के लिए कोई प्रभावी और जवाबदेह व्यवस्था मौजूद नहीं है।

स्पा की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़ पुलिस ने 5 युवतियों को छुड़ाया

मीरा रोड. मीरा रोड में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे कथित देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. बेवर्ली पार्क स्थित एएनके लग्ज़री सैलून एंड स्पा पर छापेमारी कर पुलिस ने 5 युवतियों को रेस्क्यू किया, जबकि स्पा की आड़ में देह व्यापार संचालित करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. सबसे गंभीर बात यह है कि जिस स्पा सेंटर पर कार्रवाई हुई, उसके ठीक सामने शहर का एक प्रतिष्ठित स्कूल स्थित है. स्कूल के आसपास इस तरह की अवैध गतिविधि संचालित होने से स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है तथा निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही स्पा के लाइसेंस, दस्तावेज़ों और अन्य कानूनी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अवैध कारोबार कब से चल रहा था और इसमें अन्य किन लोगों की संलिप्तता है. मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस ने आगे भी अहम खुलासों की संभावना जताई है. डीसीपी (जोन-1) राहुल चव्हाण ने बताया कि एसीपी पिंगले को इसकी सूचना मिली थी.

ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस पर पूर्ण विराम: महाराष्ट्र में नए परमिट और रिन्यूअल बंद, डांस बार कानून के तहत कार्रवाई

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस व्यवस्था पर बड़ा फैसला लेते हुए नए परमिट जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसी के साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि पहले से जारी ऑर्केस्ट्रा लाइसेंसों का नवीनीकरण भी अब नहीं किया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग ने सोमवार को परिपत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि डांस बार संबंधी कानून की पाबंदियों से बचने के लिए ऑर्केस्ट्रा लाइसेंसों का वैकल्पिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा था।

मंजूर किए गए थे संशोधन का प्रस्ताव

इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लागू किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि राज्य में महाराष्ट्र होटल व बार रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध और उनमें कार्यरत महिलाओं की गरिमा की रक्षा अधिनियम, 2016 पहले से लागू है। इस कानून के लागू होने के बाद डांस बार और नृत्य प्रस्तुतियों पर सख्त नियम लागू किए गए, जिससे डांस प्रदर्शन लाइसेंसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई।

राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आई कि कुछ प्रतिष्ठान इन प्रतिबंधों से बचने के लिए ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का वैकल्पिक रूप में उपयोग कर रहे थे। इसी दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने ऑर्केस्ट्रा प्रतिष्ठानों को भी वर्ष 2016 के इसी कानून के दायरे में लाने का फैसला किया।

इसके तहत अब ऑर्केस्ट्रा से संबंधित लाइसेंस महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के बजाय वर्ष 2016 के विशेष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही नियंत्रित किए जाएंगे।

कैबिनेट ने पहले ही दी थी मंजूरी

इस बदलाव से संबंधित कानून में संशोधन के प्रस्ताव को 2 जुलाई को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद गृह विभाग ने सोमवार को आधिकारिक परिपत्र जारी कर नए लाइसेंस जारी करने और पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण पर रोक के निर्देश लागू कर दिए। सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य कानून के दुरुपयोग को रोकना और मनोरंजन प्रतिष्ठानों के संचालन में पारदर्शिता एवं नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है।

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग हुआ सख्त, खून के कारोबार पर कड़ी नजर

राज्य में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली और रक्त के संग्रह, भंडारण और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इसके तहत अब राज्यभार में विशेष अभियान चलाकर खून के कारोबार पर बारीकी से नजर रख रहा है। इसी क्रम में राज्य रक्त संक्रमण परिषद के निर्देश पर महाराष्ट्र के 350 से अधिक ब्लड बैंकों के रिकॉर्ड, स्टॉक और लेनदेन की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है।

विशेष अभियान के तहत अंतरराज्यीय रक्त हस्तांतरण, रक्त संग्रह और वितरण के मिलान से लेकर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के पालन तक हर पहलू की पड़ताल की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर संबंधित ब्लड बैंक के खिलाफ एफडीए कार्रवाई करेगी।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. नितिन अंबाडेकर ने बताया कि प्रत्येक जिले का ब्लड ट्रांसफ्यूजन अधिकारी अपने जिले के ब्लड बैंकों की निगरानी करता है और अब उन्हें विस्तृत ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले लगभग एक माह तक जारी रह सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य में 350 से अधिक ब्लड बैंक संचालित हैं तथा प्रत्येक जिले में औसतन 10 से 12 ब्लड बैंक हैं।

जांच के दौरान यह भी परखा जाएगा कि ब्लड बैंकों में रक्त संग्रह और वास्तविक वितरण का रिकॉर्ड मेल खाता है या नहीं, ई-ब्लड बैंक डैशबोर्ड पर रक्त भंडार का विवरण नियमित रूप से अपडेट किया गया है या नहीं तथा रक्त और रक्त घटकों के प्रोसेसिंग शुल्क संबंधी सूचना बोर्ड प्रदर्शित किए गए हैं या नहीं। इसके अलावा तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता, रक्त भंडार का नियमित ऑडिट और शिकायतों के निस्तारण की भी समीक्षा की जाएगी।

ब्लड ट्रांसफ्यूजन अधिकारियों को किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर एफडीए को रिपोर्ट भेजने का अधिकार भी दिया गया है। एफडीए ही ब्लड बैंकों का लाइसेंस जारी करने वाली प्राधिकृत संस्था है। उल्लेखनीय है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत रक्त को औषधि की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इसके संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण में गुणवत्ता, सुरक्षा तथा पारदर्शिता बनाए रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर में ब्लड बैंकों के औचक निरीक्षण के लिए तीन सदस्यीय समितियों का भी गठन किया है। इन समितियों में दो चिकित्सा अधिकारी, एक लेखा अधिकारी और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. नितिन अंबाडेकर ने कहा कि प्रत्येक जिले का ब्लड ट्रांसफ्यूजन अधिकारी अपने जिले के सभी ब्लड बैंकों का ऑडिट कर रहा है। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले लगभग एक महीने तक जारी रहेगी। जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित मामले की रिपोर्ट एफडीए को भेजी जाएगी।

'नशा मुक्त मुंबई' पर राज्य सरकार का जोर अभियान में सबकी भागीदारी जरूरी : लोढ़ा

मुंबई : 'नशा मुक्त मुंबई' अभियान गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुभारंभ करेंगे. यह सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी को बढ़ते ड्रग्स की लत से बचाने के लिए लगातार चलने वाला सार्वजनिक शिक्षा और जनहित अभियान है. कौशल विकास मंत्री और मुंबई उपनगर जिला के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने जोर देकर कहा कि समाज के सभी वर्गों, खासकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अभियान में शामिल होना चाहिए. 'नशा मुक्त मुंबई' अभियान 30 जुलाई को वर्ली डोम में शुभारंभ किया जा रहा है और वे उसी के बैकग्राउंड में सोमवार को आयोजित समीक्षा मीटिंग में बोल रहे थे. इस मौके पर उपनगर जिलाधिकारी सौरभ कटियार, मुंबई शहर जिलाधिकारी आंचल गोयल (ऑनलाइन) के साथ बीएमसी प्रशासन, स्कूल विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, बीएमसी के अधिकारी, अलग-अलग एजेंसियों और सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि मौजूद रहे. मीटिंग में मंत्री लोढ़ा और जिलाधिकारी कटियार ने अभियान को आयोजित करने के लिए संबंधित एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए.

हिन्दी प्रचार शोध संस्थान, मुंबई मीरा भाईंदर महानगरपालिका की नवनियुक्त शिक्षण, कला क्रीड़ा, सांस्कृतिक सभापति सौ स्नेहा शैलेश पांडे का जाहिर नागरिक अभिनंदन समारोह सम्पन्न

हिन्दी प्रचार शोध संस्थान, मुंबई द्वारा संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉ॰ सुधाकर मिश्र जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में मीरा भाईंदर महानगरपालिका की नवनियुक्त निर्विरोध चुनी गई शिक्षण, कला क्रीड़ा, सांस्कृतिक सभापति सौ स्नेहा शैलेश पांडे का जाहिर नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया।व साथ ही प्रति माह की तरह हिन्दी प्रचार एवं शोध संस्था की 262 वीं गोष्ठी संपन्न हुई।

जिसमे अध्यक्ष डॉ सुधाकर मिश्र, सम्मान मूर्ति श्रीमती स्नेहा शैलेश पाण्डेय, समारोह संयोजक डॉ उमेश चन्द्र शुक्ल, कवि सम्मेलन संचालन विजय नाथ मिश्र सरस्वती वंदना शिव प्रकाश जमदग्नि पुरी ने किया। मासिक काव्य गोष्ठी समारोह भी आयोजन किया गया। हिन्दी प्रचार एवं शोध संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉ सुधाकर मिश्र जी ने शिक्षण सभापति के सत्कार के उपरांत उनके व्यवहार कुशलता, सादगी एवं सेवा कार्यों की प्रशंसा की तथा शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक कार्य करने का आशीर्वाद दिया।

शिक्षण सभापति स्नेहा पांडे ने अपने वक्तव्य में सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, आने वाले समय में आप सभी साहित्यकारों के मार्गदर्शन मे हमें साहित्य, शिक्षा जगत में अनेक कार्य करने हैं। आपके सुझाव मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद हमेशा सेवा कार्य के प्रति प्रेरणादायक रहेंगे।

समारोह में प्रमुख रूप से भाजपा प्रवक्ता आचार्य शैलेश पांडे राष्ट्रीय कवि डॉ. सुरेश मिश्र, प्रो श्रीधर मिश्र, अजीत शुक्ल प्रबंधक मारुती ज्युनियर कॉलेज, डॉ.ओम प्रकाश तिवारी डॉ.प्रमोद पल्लवितविजय नाथ मिश्र, डॉ लक्ष्मण शिवणेकर ,शिव प्रकाश जमदग्नि पुरी, हीरालाल विमलेश झा ,लालबहादुर यादव, अरुण दुबे ,श्रीमती लक्ष्मी यादव ,विनोद कुमार शुक्ल ,उपेंद्र पाण्डेय,माता कृपाल उपाध्याय, शारदा प्रसाद दुबे ,शरतचन्द्र, आर.पी.सिंह, डॉ.अशोक पाण्डेय, दिनेश दुबे उद्योगपति आदि मान्यवर कविगण , साहित्यकार उपस्थित रहे।

मीरा-भायंदर और पालघर की राजनीति में बड़ी हलचल!

संदीप भास्कर सावंत

सूत्रों के अनुसार, युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस में नवज्योत सिंह (बॉबी) को कोंकण विभाग, पालघर जिला और मीरा-भायंदर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा तेज़ हो गई है। पार्टी के भीतर संगठनात्मक स्तर पर सकारात्मक माहौल बताया जा रहा है। आधिकारिक घोषणा आने वाले दिनों में होने की संभावना जताई जा रही है।

सुनील तटकरे, संजय बनसोडे, ज़ीशान सिद्दीकी, वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में नवज्योत सिंह (बॉबी) युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव के पद को न्याय देने का प्रयास करेंगे।

मीरा-भाईंदर में भी मनाया कारगिल विजय दिवस

कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मीरा-भाईंदर में आयोजित कार्यक्रम में जेन जी छात्र, युवा, अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए. कार्यक्रम की शुरुआत कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई. इसके बाद नीट पेपर लीक मामले में प्रभावित छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई. कार्यक्रम के अंत में युवाओं ने संकल्प लिया कि छात्रों के भविष्य से जुड़े किसी भी अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज़ शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप आगे भी बुलंद रहेगी. साथ ही कारगिल के शहीदों के आदर्शों को याद करते हुए राष्ट्रहित और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

7 दिन में समाधान नहीं तो संविदा कर्मी करेंगे कामबंद हड़ताल MBMC उपायुक्त कार्यालय का घेराव

भाईंदर : मीरा-भाईंदर मनपा के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने सोमवार को 3 माह का बकाया वेतन और लंबित मांगों को लेकर मनपा उपायुक्त सचिन बांगर के कार्यालय का घेराव किया. श्रमजीवी कामगार संघ के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान मनपा प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित अवधि में मांगों का समाधान नहीं हुआ तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत सभी संबंधित कर्मचारी कामबंद हड़ताल पर चले जाएंगे. संघ के मनपा यूनिट के अध्यक्ष मंगेश डी. मोरे ने मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा और महापौर डिंपल मेहता को सौंपे ज्ञापन में कहा कि विभिन्न विभागों के संविदा कर्मचारियों की मूलभूत मांगें, बकाया वेतन और वैधानिक देयक वर्षों से लंबित हैं.

इन मुद्दों को लेकर कई बार ज्ञापन, पत्राचार और बैठकों के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. संघ ने स्पष्ट किया कि यदि 7 दिनों के भीतर कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो पूरे मनपा में संवैधानिक अधिकारों के तहत कामबंद आंदोलन किया जाएगा. संगठन का कहना है कि आंदोलन के दौरान यदि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मनपा प्रशासन और संबंधित ठेकेदारों की होगी.

विश्व मैंग्रोव दिवस पर मीरा-भायंदर में 750 किलो कचरा हटाया निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर युवाओं की पुलिस से शांतिपूर्ण अपील

मीरा-भायंदर: विश्व मैंग्रोव दिवस के अवसर पर शनिवार को भायंदर (पूर्व) के जैसल पार्क खाड़ी क्षेत्र में फॉर फ्यूचर इंडिया, मैंग्रोव फाउंडेशन और महाराष्ट्र वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विशाल मैंग्रोव सफाई अभियान आयोजित किया गया। अभियान में 100 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लेकर मैंग्रोव क्षेत्र से लगभग 750 किलोग्राम कचरा हटाया।

इस अभियान में पाटकर कॉलेज, एलआरएमसी कॉलेज और रॉयल कॉलेज की एनएसएस इकाइयों के विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। मीरा भायंदर महानगरपालिका के स्वच्छता विभाग ने भी अभियान में सहयोग किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने मैंग्रोव के संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण और तटीय सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जानकारी दी।

सफाई अभियान के बाद युवाओं ने मैंग्रोव विनाश से जुड़े मामलों की जांच में कथित प्रक्रियागत त्रुटियों और पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि कुछ मामलों में मुख्य आरोपियों को जांच से बाहर रखने तथा कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण पालन न होने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पर्यावरणीय अपराधों की निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनसम्मत जांच की मांग की।

फॉर फ्यूचर इंडिया के संस्थापक एवं अध्यक्ष हर्षद ढगे ने कहा, 'हमारी मांग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरणीय अपराधों में दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई हो। यही पर्यावरण न्याय की बुनियाद है।' युवाओं ने पुलिस प्रशासन से वर्ष 2005 से 2025 के बीच पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज 200 से अधिक मामलों का विशेष ऑडिट और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विरोध नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जांच प्रक्रिया में जनविश्वास बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण पहल है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा।

आषाढी एकादशी के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों को प्रसाद वितरित

भायंदर। देश के सुप्रसिद्ध समाजसेवी तथा और राहुल एजुकेशन के चेयरमैन पंडित लल्लन तिवारी द्वारा अपने माता-पिता की स्मृति में भायंदर पूर्व के आरएनपी पार्क में बनवाए गए भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर में आषाढी एकादशी के अवसर पर भक्तों को खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। युवा समाजसेवी कमलेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह के सौजन्य से आज के प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में मंदिर के ट्रस्टी पुरुषोत्तम पांडे, वरिष्ठ नगरसेवक मदन उदित नारायण सिंह, शारदा प्रसाद पांडे, श्री राम दुबे अजय मिश्रा, पप्पू तिवारी, वीरेंद्र पाठक सुधाकर पांडे, बबलू पांडे, शिव पांडे आदि का समावेश रहा। यहां हर शनिवार को किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से खिचड़ी या अन्य प्रसाद का वितरण किया जाता है। आगामी शनिवार (1 अगस्त) को पंडित राकेश मणि त्रिपाठी लंदन वाले के सौजन्य से खिचड़ी का वितरण किया जाएगा।

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com